

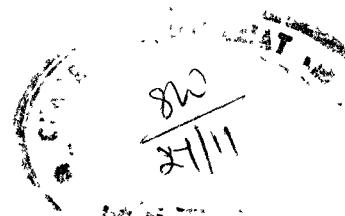


भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्रधानमंत्री से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 131]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 1989/आषाढ़ 28, 1911

No. 131]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 1989/ASADHA 28, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1989
मंकल्प

मंख्या 13-33/85-सी.एच.आर. (ग.मो.)—ग्राहिक संख्या 1171
(मी.आर.एन.), 1982 में, अपने दिनांक 6-2-1984, 27-9-85
और 3-12-1986 के निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मानदंड और
सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए और
वह प्रक्रिया भी निर्धारित की है जिसे बच्चों के अन्तर्राष्ट्रीय दरक ग्रहण
के प्रयोग मामले में अन्याय जाना चाहिए। इन मानदंडों, मिद्दानों और
प्रक्रिया के मुविवाजनक कार्यालय के लिए भारत दरकर, जन संघारण,
स्वयंसेवी संगठनों और इस विषय से मंवंदित अन्य सभी की सूचना और
मर्दिष्ठन के लिए इस संकलन के अनुबन्ध-1 के अनुसार, बच्चों के
दसक ग्रहण के मंबेडी मिद्दान जरी करती है।

अनुबन्ध 1

कल्याण मंत्रालय

भारतीय बच्चों के उच्चतम ग्रहण मंबेडी मामलों के विनियमन हेतु दिन
निर्देश

1. उद्देश्य एवं लक्ष्य—भारत मरकर का मन है कि समाज का
कल्याण, इमारा विकास कार्य हद तक उम्मेके बच्चों के स्वास्थ्य और
कल्याण पर निर्भर करता है। मारन के मंवंदित में इन बात की व्यवस्था
की गई है कि रज्य अन्य बातों के माध्यम से, अपनी नीति में स्वास्थ्य-

कर तरीकों से बच्चों के विकास की सुविधाएं प्रदान करने और स्वतंत्रता
और प्रविष्टि के महील में रहने की व्यवस्था करेगा और बच्चों और
युवकों को शोषण और नीतिक तथा ग्राहिक परिव्याप्ति के विरुद्ध संरक्षण
प्रदान करेगा। राष्ट्रीय बाल नीति यह भी स्वीकार करती है कि राष्ट्र
के बच्चे मर्वाइक महत्वपूर्ण परिमंति है और उनका पोषण और
देखभाल राष्ट्र का दायित्व है।

1.2 बच्चों के विकास के लिए परिवार महायना की अवश्यकता—
यह एक मान्य तथ्य है कि बच्चे का संतुलित विकास, भावनात्मक शारीरिक
ओर बौद्धिक, परिकार में ही अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा
सकता है या जहा यह संभव नहीं है ऐसे बच्चों—जिनमें अन्यथा, परिवर्कत
उपेक्षित और जागित बच्चे जातियाँ हैं, की देखभाल और संरक्षण पारिवारिक
व तत्वरण में करने की विमेदरी मुश्यतः परिवर्त, समृद्धि और
अमर नमज की है। तथापि परिवर्त र मुश्यतः महिल अधिकारां परंपरागत
मंस्यानों में शैक्षणिक औद्योगिक करण और विहर मकी न मान्य प्रक्रिया
के कारण परिवर्तन हो रहे हैं। बच्चे की पारिवारिक महायना सदैव
उपलब्ध नहीं होते। अब निर्धारित बच्चों की मंस्यागत और गैर-मंस्यागत
महायना प्रदान करने के उपाय यित्व समृद्धि, नमज और गैर-गैर-मंस्यागत
महायना प्रदान करने वाले जैसी विधियाँ नहीं होती हैं। परंपरागत मामले में हमारा नमज धर्मविर्ति संस्थाओं और
गैर-मंस्यागत कर्तव्यपूर्णों के द्वारा अन्य और निम्नलिखित बच्चों को मंवंदित
प्रदान करना चाहे है। दसक ग्रहण संरक्षण और पोषण, देखभाल जैसी
मेवांगी गैर-मंस्यागत माध्यम में निम्नलिखित बच्चों की उपलब्ध होती रही
है। मामले जिक इनमें नीति परिवर्तन होने से और अन्य मंवंदित कार्यों के
फलस्वरूप ऐसे बच्चों की मंस्या, में वृद्धि हो रही है जिन्हें देखभाल, संरक्षण

और पुनर्वासी की आवश्यकता है। अतः ऐसे बच्चों के प्रोत्तर के लिए केवल संस्थागत और गैर-संस्थागत मुद्रिताओं में विनाउर बरता हो आवश्यक नहीं है परन्तु बाल कल्याण संबंधित सभी कार्यक्रमों को नियमित व गुजार स्वरूप से बचाना और उनकी मोनिटरिंग करता भी आवश्यक है ताकि सभी बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम भानक मुनिशित छिपा जा सके। वैर संस्थागत तरीकों से से, बच्चे को परिवार में रखने से बच्चे के हित बहुत मुरझित हो जाते हैं। यह भी एक स्वीकार्य नहीं है कि बच्चा अपनी मस्तुकी और मामाजिक बातावरण में अच्छा विकास बरता है। अतः बच्चों का अपने निजी बातावरण में ही किसी अच्छे परिवार द्वारा दत्तक ग्रहण बरता उसके विकास के लिए बहुतम है। अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण अवश्य भास्तीय बच्चों को भावी विदेशी माना-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए केवल ऐसी प्रवृत्त्या में देता जाहिं जबकि भास्तीय माना-पिता उपनिवेश करने के सभी प्रवास प्रसकृत हो जाएँ। मामाजिक चाहे स्वदेश में हींगों विदेश में, दत्तक ग्रहण में संबंधित सभी मामलों में बच्चे का कल्याणार्थ किन गवर्नेंसि होना चाहिए।

1.3 इनके ग्रहण की प्रणाली की समीक्षा ——प्रस्तराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के मामलों में अपनाई गई बर्तमान कार्यप्रणाली और प्रवृत्त्यों की विस्तृत समीक्षा उच्चतम न्यूनतम द्वारा दिया गया अपने विनाउर 6 फरवरी, 1984 तथा 1985 और 3 दिसंबर 1986 के निर्णयों में की गई है। यह निर्णय श्री जयमीठांपुरावं अध्यक्षन के सभी प्रवास प्रसकृत (नी आर एम) 1171/1982 के संबंध में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अवधारणों पूर्वक अध्यक्षन के बाल कल्याण मानालय भारत सरकार न्यूनतम स्वरूप में बाल कल्याण को प्रोत्तर, हित करने विदेश-वाले दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चे के विकास को मुनिशित करने के लिए विनाउर दिया निर्देश निवारिंग करती है ——

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित देशों के प्राप्तानों की भूमिका

2.1 बलिगुडा की सूची ——राज्य सरकारें (राज्य सरकारें शब्द में जहाँ कही लगू हो) केन्द्र या निर्देश प्रदेश प्रश्न सत्र शासित होगे) विभिन्न कानूनों के प्रस्तरांत लाइसेंसदा प्रश्नकृत प्रवासी मन्त्र ब्राह्मण कल्याणी व सभी संस्थाओं की जिम्में निजी व अन्य सकारात्मक सम्पादन संभितियां होंगी जो निर्धित, प्रश्नकृत, अनाधी, किशोर अवसराधी और उपेक्षित बच्चों के लिए जारी होंगी, एक सूची रखेंगी।

2.2 इनके ग्रहण एजेंसियों की सूची ——राज्य सरकारें देश में और देश में बाहर बच्चों के इनके ग्रहण में संबंधित सभी एजेंसियों को अलग से एक सूची रखेंगी।

2.3 इनके ग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण ——राज्य सरकारें देश में और देश के भावाव इनके ग्रहण में संबंधित सभी एजेंसियों और भागठनों और भच्चों की सेवाओं से संबंधित कार्यक्रमों/गतिविधियों से संबंधित सभी कागजान, दस्तावेजों का समय-समय पर निरीक्षण निभाना जाना करने हेतु रखेंगी ——

- (1) कि मस्ता द्वारा इनके ग्रहण का कार्य बच्चों के हित में एक कल्याण कार्य के रूप में किया जा रहा है न कि आपार के रूप में।
- (2) गृही म दाखिल किए गए बच्चों का उच्चत रिकॉर्ड देश जा रहा है।
- (3) दाखिल किए गए बच्चों का उच्चत रिकॉर्ड देश जा रहा है।
- (4) बच्चों को इनके ग्रहण करने में संलग्न में लिए रखने वाले अधिकारी का सूची माना द्वारा निर्देश द्वारा देश में रखी जाएँगी।

(5) भागठन के लिए रखे जा रहे हैं और विना विलम्ब के लिए परीक्षा कराई जानी है। लेकिन परीक्षा की रिपोर्ट संतोषजनक है, एजेंसियों से प्राप्त धनराशि प्राप्त करने वाले भागठन गृह मानालय के माध्यम द्वारा विधि पंजीकृत हैं और उन्होंने विवेदी अधिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 का प्रत्यावर्तन किया है।

(6) संगठन एजेंसियों में दत्तक ग्रहण करने से पहले देश में दत्तक ग्रहण हेतु प्रीमियम के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

(7) भागठन दत्तक ग्रहण में दिए गए बच्चों के हितों के संबंध में नियमित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है और देश से बाहर उनके हितों के मंत्रालय हेतु पर्याप्त अनुबर्ती उपाय करता है, और

(8) बच्चों की देशभाव के लिए मामाजिक कार्य का अनुभव रखने वाले स्टाफ को रखा जाना जारी है।

2.4 इनके ग्रहण समीक्षा ममिति ——प्रत्येक राज्य सरकार, एक इनके ग्रहण समीक्षा ममिति की स्थापना करेंगी और उस में राज्य सरकार का प्रतिनिधि अवश्य होगा। इस समिति में मान्यताप्राप्त भारतीय व्यवस्था एजेंसियों, जांच एजेंसियों और आवश्यकतानुसार दत्तक ग्रहण और बाल कल्याण मामलों के विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बाल कल्याण उपायों विवेषकर, देश में बाल दत्तक ग्रहण की प्रशंसिति के उपायों के संबंध में विकार करने हेतु समिति की समय-समय पर बैठक होंगी। राज्य सरकारें इनके ग्रहण कार्य के मान्यताय, विनियम और विकास और दत्तक ग्रहण समीक्षा ममिति की सभी योग्यता प्रदान करने के लिए समाज कल्याण निवेशलय में दत्तक ग्रहण संलग्न की स्थापना भी करेंगी।

2.5. नियोजन का प्रबोधन ——इन एजेंसियों के कार्यकरण का प्रबोधन तथा सूचीकरण करने के लिए राज्य सरकार इनके ग्रहण में कार्यरत सभी एजेंसियों ने प्रत्येक नियमी ही में सूचना तथा आंकड़े बंगवारपंथी। ये आंकड़े इस प्रयोजन हेतु निर्धारित किए जाने के लिए प्रयोग में लाना जाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय बाल दत्तक ग्रहण को संभिय रूप से प्रोत्तराहित करने के लिए राज्य सरकारें सभी उपाय करेंगी जो आवश्यक हो तथा दत्तक ग्रहण के माध्यम से अन्यायालयों में यह ऐसे बच्चों के पुनर्वाप पर विशेष ध्यन दिया जाएगा।

किशोर एवं अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियांत्रित कार्रवाई

3.1. सभी नियम गृही तथा अस्पतालों, धार्मिक संस्थाओं इत्यादि भवित्व परिक्षियों अंतर्गत एजेंसी अधिकारी दत्तक ग्रहण की परिवर्तन अवधारणा निरापत्ति बच्चे कही न जार आते हैं अथवा वे ऐसे बच्चों को अपने परिसरों/सेवाओं में परिवर्तन पाए अथवा अन्यथा, वे ऐसे बच्चों की प्राप्ति अथवा मिलने से संबंधित सूचना, जहाँ ऐसे निर्माण होम अथवा प्रस्तावल राज्य की राजधानी में विद्य है, तुरंत संबंधित सरकार के समाज कल्याण विभाग को देंगे तथा अन्य मामलों में जिले के कलेक्टर को वे तथा ऐसी सूचना की पतियां पालन पोषण देशभाव गृह, जहाँ कही ऐसे, गृह सरकार द्वारा अन्याया जा रही हो, और सभी वे उस नगर अथवा कस्बे में कार्य कर रही सामाजिकप्राप्ति विभाग की राजधानी में विद्य है, तुरंत संबंधित सरकार के समाज कल्याण विभाग को देंगे तथा अन्य मामलों में जिले के कलेक्टर को वे तथा ऐसी सूचना की पतियां पालन पोषण देशभाव गृह, जहाँ कही ऐसे, गृह सरकार द्वारा अन्याया जा रही हो, और यदि अथवा कस्बे में कार्य कर रही सामाजिकप्राप्ति विभाग अस्पताल स्थित हो और किशोर एवं अधिनियम 1986 के अन्तर्गत गठित किशोर कल्याण बोर्ड को भी भेजेंगे। समाज कल्याण विभाग तथा साथी ही जिले का कलेक्टर भी इस काल को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देंगे; कि उनके कर्यक्रम में अपने वाले निर्माण गृह तथा अस्पताल इन्हें इस निवेश को पालन करें और यदि अथवा कस्बे में संबंधित बच्चों के पता लगें/मिलने के संर्वत्र में सूचना, यदि किसी विशेष निर्माण गृह अथवा प्रस्ताव ल द्वारा पालन पोषण देशभाव गृह तथा सामाजिकप्राप्ति विभाग एजेंसियों का न भेजी गई हो, तो उन्हें समाज कल्याण विभाग तथा जिले का कलेक्टर द्वारा भेजी जाएगी।

3.2. प्राधिकृत व्यक्तियों इत्यादि द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :— यदि किसी व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन जिन्हें परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चा मिलता है अथवा संपैगा जाता है, को राज्य सरकार द्वारा परिषद्वन् छोड़ दिए गए बच्चे की देखभाल के लिए प्राधिकृत किया गया है तो एसा व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन परित्यक्त शिशु के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 अथवा किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत उपेक्षित किशोर के संबंध में उपेक्षित कार्रवाई करेगा तथा शिशुओं के मामले में उचित टैग लगाकर बच्चे की पर्याप्त पहचान भी सुनिश्चित करेगा।

3.3. प्राधिकरण हेतु आवेदन :— बाल कल्याण कार्यकलापों में कार्यरत कोई व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन जो परित्यक्त शिशुओं अथवा उपेक्षित किशोरों की देखभाल करना चाहता है अथवा जो सुरक्षित स्थान अथवा योन्य व्यक्ति/संस्था के रूप में कार्य करना चाहता है, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 अथवा किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार को आवेदन करेगा।

3.4. सूचियां बनाना तथा परिचालित करना :— राज्य सरकार एसे सभी व्यक्तियों, एजेंसियों अथवा संगठनों की सूची बनाएगी जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम, 1986 अथवा किसी कानून के अन्तर्गत परित्यक्त बच्चों अथवा उपेक्षित किशोरों को देखभाल करने अथवा सुरक्षित स्थानों अथवा योन्य व्यक्तियों संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इन सूचियों को उन पुलस अधिकारियों तथा किशोर कल्याण बोर्ड की भेजेगी जिनकी सामग्री के अन्तर्गत ये व्यक्ति, एजेंसियों अथवा संगठन स्थित हैं।

3.5. बच्चे की व्यक्तिगत उपस्थिति :— किसी परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चे के मिलने अथवा अधिकार में लिए जाने वे बारे में किशोर कल्याण बोर्ड अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित करते समय उन्हें बच्चे को किशोर कल्याण बोर्ड अथवा किसी प्रत्ये उपयुक्त प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित करना आवश्यक नहीं है जब तक कि किशोर कल्याण बोर्ड अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसा निर्देश न दिया जाए।

3.6. योग्य व्यक्ति/संस्था पर नियंत्रण :— राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यदि नर्सिंग गृह, अस्पताल, धार्मिक संस्था इत्यादि सहित किसी व्यक्ति, एजेंसी अथवा संगठन को बच्चे की बिक्री, खरीद, उर्वरक्षा, अत्याचार में अत्यस्का पाया जाए अथवा जिस बच्चे के देखभाल की किसी भी रूप में जिम्मेदारी ली हो उसकी देखभाल में उपेक्षा करते हुए पाया जाए, तो कानून के अनुसार उस व्यक्ति (ओं) के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा।

बाल दत्तक ग्रहण में कार्यरत भारतीय एजेंसियों की भूमिका

4.1. प्राधिकारियों के साथ सूचीकरण :— बच्चे की देखभाल एवं अभिभावक अथवा दत्तक ग्रहण कार्य, अथवा अनाथों, परित्यक्तों, निराश्रितों, उपेक्षितों अथवा छोड़ दिए गए बच्चों से संबंधित किसी अन्य कार्यकलाप में कार्यरत प्रत्येक संस्था तुरन्त प्रत्येक को संबंधित राज्य सरकार के साथ सूचीबद्ध करवाएगी।

4.2. दत्तक ग्रहण का कार्य केवल मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा किया जाना :— अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण कार्य करने का इच्छुक कोई भी भारतीय मान्यताप्राप्त करने हेतु भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का अविदेन वर्षां एजेंसियों जो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से मान्यताप्राप्त हैं, अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण कार्य करेंगी।

4.3. बाल कल्याण पर बल :- केवल ऐसी एजेंसीयों ही अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु कल्याण मंत्रालय को अविदेन करें जो मुख्यतः बच्चों के विकास तथा प्रोत्संहार के लिए बाल कल्याण कार्यक्रमों में कार्यरत हों तथा जो दत्तक ग्रहण को अपने समार्थक कार्यकलापों का एक भाग मानती हों।

4.4 भारी दत्तक याही मातापिता की सूची :— दत्तक ग्रहण में व्यवस्था कार्य करने के लिए मान्यताप्राप्त प्रत्यक्त समाज/बाल कल्याण संगठन नियमित रूप में सभी भारी मातापिता की सूची बनायेगा जिसमें उनके नाम, पते, बाल दत्तक ग्रहण करने हेतु संगठन में समर्च करने जी तरिख तथा अन्य प्रामाणिक व्यापार होगा।

4.5 देश के अन्दर दत्तक ग्रहण का संबद्धन :— प्रत्येक मान्यता प्राप्त एजेंसी बच्चे के एक भारतीय परिवार द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए नभी संभव प्रयाप करेगी तथा भारी दत्तकप्राहृष्ट परिवार को बच्चे के गवाह में सम्पूर्ण विवरण देगा परन्तु वह मान्यताप्राप्त एजेंसी को बच्चे के वास्तविक मातापिता के नाम व पते मानूस भी द्दो तो भी दत्तकप्राहृष्ट परिवार को यह तही बताए जाएगे।

4.6 संबद्धन प्रयापों का रिकार्ड :— प्रत्यक्त मान्यताप्राप्त एजेंसी कानूनानुसार, उनके द्वारा बच्चे के एक भारतीय अभिभावक द्वारा दत्तक ग्रहण के संबंध में किए गए प्रयापों का पूरा रिकार्ड रखेगा और यदि किसी बच्चे के भारतीय अभिभावक द्वारा न अपनाए जाने या दत्तक ग्रहण करने का मामला मामने आता है तो दत्तक न लेने के कारणों का भी रिकार्ड रखा जाएगा।

4.7 केम इतिहास :— प्रत्येक मान्यताप्राप्त व्यवस्था एजेंसी प्रत्येक बच्चे के संबंध में एक अनग पाठ्य फाइल रखेगी और इसमें बच्चे के केम का मापूर्ण इतिहास रखेगा।

4.8 प्राधिकारियों को मामिक/वेमानिक आंकड़े प्रस्तुत करना :— प्रत्येक मान्यताप्राप्त व्यवस्था एजेंसी जिस राज्य में कार्यरत है उस राज्य की सरकार को मामिक आंकड़े प्रस्तुत करेगी भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय को वेमानिक विवरण भेजेगी। ये आंकड़े और विवरण एक निर्धारित प्रपत्र में दिए जाएंगे जो गोद लेने के लिए भारतीयों और अन्यों को दिए गए बच्चों से संबंधित होगा।

भारतीय एजेंसियों को मान्यता

5.1. आवेदन पत्र के लिए प्रपत्र :— अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण कार्य के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक किसी भी भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसी को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय को निश्चिरित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। यह आवेदन पत्र उम राज्य के समाज कल्याण मंत्रालय विभाग के मान्यता से भेजा जाना चाहिए जिसमें यह एजेंसी कार्यरत है।

5.2. गैर मान्यता प्राप्त एजेंसियों पत्र रोक :— कोई भी ऐसी एजेंसी जिसके पास कल्याण मंत्रालय से मान्यता का प्रमाण पत्र नहीं है, किसी भारतीय व्यायालय में अभिभावक और संरक्षक अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत एक भारतीय बच्चे के लिए एक विदेशी को अभिभावक घोषित करने के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकेगी।

5.3. विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता :- कल्याण मंत्रालय मान्यता, किसी भी एजेंसी को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता देगा। मान्यता प्रमाण-पत्र जारी होने तक मंत्रालय द्वारा इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

5.4. देश के अन्दर दत्तक ग्रहण का नियन :— प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्वचित एजेंसी का यह कर्तव्य होगा कि वह कम से कम अपनी मान्यता के प्रथम वर्ष के दौरान गोद लेने अभिभावकत्व के रूप में कोई व्यवस्था में से कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को भारतीय घरों के अन्दर हो स्थान दिलवाये। देश के अन्दर बच्चों को गोद लिए जाने या अभिभावकत्व का यह स्तर मान्यता के तीसरे वर्ष तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यदि एजेंसी उपरिनियन्त्रित आकारों के अनुमान देश के अन्दर बच्चों के दत्तक ग्रहण के कार्य में अमरकृत रहती है तो एजेंसी को दी गई मान्यता वापस भी दी जा सकती है। तथापि मान्यता वापस लेने से पूर्व ऐसी एजेंसी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे।

5.5 मान्यता की शर्तें - मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक एजेंसी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी -

(क) सोमावधी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत यह सोमावधी पंजीकृत हो या असाधारण अधिनियम के अन्तर्गत न्याय बनावा गया हो अथवा सहमा किसी उपयुक्त कानून के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(ख) सगठन राज्य मरकार द्वारा बात कल्याण सगठन के स्थ मध्यावधि सूचीबद्ध हो।

(ग) इसको यथाविधि गठित वार्यकारियों भर्मित हो। सगठन के मुख्य कार्यकारी के अनिक्षिक बोर्ड/कार्यकारिणी के अधिकाश मद्दस भारतीय हो।

(घ) यह राज्य सरकार द्वारा यथाविधि सूचीबद्ध सगठन हो जिसके पास शिशु महिल बच्चों के मरकार तथा भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था हो।

(ङ) सगठन पिछले तीन वर्षों के दोगांन मावैजनिक दान द्वारा धन-राशि एकात्मक करने में सक्त हुआ हो।

(च) पिछले तीन वर्षों के दोगांन सगठन बच्चों के कल्याण मध्यरत रहा हो।

5.6 एजेंसी लेखा रखेंगी - (1) एजेंसी प्रत्येक वर्ष अनदी लेखाकार द्वारा लेखा-परीक्षण के लिए उपयुक्त लेखे रखेंगी।

(2) प्रत्येक एजेंसी लेखा-परीक्षण लेखा की एक फोटो प्रति के माध्यम से अनदी लेखाकार द्वारा लेखा-परीक्षण लेखा की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का लेखा-परीक्षण के बाद एक माह के भीतर सबद्ध राज्य मरकार के मामाज कल्याण विभाग को तथा कल्याण मवालय भारत मरकार द्वारा भी भेजेंगी।

5.7 आवेदन पत्र पर केवल पंजीकृत एजेंसी द्वारा कार्रवाई - एक विदेशी या एक भारतीय को विदेश में भारतीय बच्चों के मरकार की अधिकाश करने के आवेदन पत्र पर कवन मान्यताप्राप्त एजेंसी द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी।

5.8 आवेदन पत्र सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी द्वारा प्रायोजित हो - मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी विदेश दिलक ग्राही मान्यता-प्रिता का आवेदन पत्र किसी भारतीय न्यायालय में भारतीय बच्चों का मरकार कल्याण विदेशी को शौपने के सबध म दे सकती है वज्रन ऐसे विदेशी आवेदन पत्र भारत मरकार कार द्वारा सूचीबद्ध विदेशी सूचितक सगठन द्वारा अप्रेवित किया गया हो। यदि विदेश में भारत सरकार द्वारा स्वामित्व दाने या सचालित सगठन हो तो विदेशी दिलक ग्राही मान्यता-प्रिता विदेशी मरकार द्वारा सचालित या स्वामित्व दानी ऐसी एजेंसी के माध्यम से मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी से सम्बद्ध कर सकते हैं।

5.9 अनुमोदित विदेशी एजेंसियों से महत्वपूर्ण भारतीय मान्यताप्राप्त एजेंसिया - कोई भी मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसी केवल भारत मरकार द्वारा सूचीबद्ध विदेशी एजेंसी के अनिक्षिक किसी विदेशी या विदेशी व्यक्ति के प्रतिनिधि में भारतीय बच्चे के दिलक ग्रहण के लिए सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करेगी।

5.10 एजेंसी का निर्गतक्षण - मान्यताप्राप्त भारतीय एजेंसिया द्वारा परिसर, जिसमें उनके बालगुह तथा उनका रिकार्ड शामिल है भारत सरकार के अधिकारियों के लिए, किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

बच्चों के दिलक ग्रहण में काथरन विदेशी एजेंसियों की भर्मिता

6.1 विदेशी एजेंसी भारतीय दूतावासों को आवेदन कर - विदेश दिलक ग्राहा मान्यता-प्रिता भारतीय बच्चे दिलक ग्रहण के लिए आवेदन पत्र

को प्रायोजित करने की इच्छुक विदेशी सामाजिक बाल कल्याण एजेंसी उन देशों में भारतीय दूतावास के वार्यालय में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र देंगी तथा केवल ऐसी विदेशी एजेंसी जो भारत मरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए सूचीबद्ध की गई है, यह बाबताई करेगी।

6.2 विदेश ले जाए गए बच्चे के अधिकार विदेशी मान्यता-प्रिता द्वारा उम देश के बानुओं के अनुसार बच्चे के दिलक ग्रहण के प्रश्न, यह माना जाएगा कि बच्चे की स्वामित्विक स्थिति में पैदा हुए बच्चे का तरह ममान सामाजिक स्तर, उन्नाधिकार, विश्वसन तथा वही गान्धीयना प्राप्त होगा जो कि बच्चे को दिलक ग्रहण करने वार मान्यता-प्रिता की है।

6.3 भारत मरकार द्वारा सूचीबद्ध कोई विदेशी सामाजिक बाल कल्याण एजेंसी कल्याण मवालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति से भारत म प्रतिनिधि निवृत्त कर मकानी ह बजाने गेमा प्रतिनिधि - 1-भारतीय नामांकित है,

2-समाज कल्याण कार्य में श्रहता प्राप्त हो तथा बाल कल्याण में अनुमत रखता हो।

3-केवल एक सूचीबद्ध विदेश एजेंसी का प्रतिनिधि हो।

4-प्रति कार्यक्षेत्र को भारत में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र नक ही संभित रखता हो, तथा

5-प्रति प्राधिकारी की अनुमति से विदेशी सूचीबद्ध सगठन के नाम पर भारत में बैंक खाता चलाने का अधिकार रखता हो।

6.4 सभी सूचीबद्ध विदेशी एजेंसिया निष्पारित प्राप्त में उम देश जहा एजेंसी स्थित है, में भारतीय दूतावास के माध्यम से कल्याण मवालय भारत मरकार को अद्वैत-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

7.1 स्वैच्छिक नमन्यव्यक्तारी एजेंसिया - राज्य या बड़े शहरों में जहा अनक सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसिया है एक केन्द्रीकृत समन्वय-कारों सगठन होगा तथा प्रत्येक सामाजिक बाल कल्याण एजेंसी दिलक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों के सबध में केन्द्रीकृत एजेंसी की सूचनाए उपलब्ध करवाएगी। गाज्य सरकार स्वैच्छिक समन्वयकारी एजेंसी के गठन के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

7.2 वार्षिक बैंक - कल्याण मवालय पारम्परिक हित के मामनो पर विचार करने तथा ऐसे अन्न मामनों जो कि आवश्यक तथा उचित ममजे जाए, पर विचार-विमर्श के लिए सभी रवैचित्रक समन्वयकारी एजेंसियों की बैठक प्रतिवाप आयोजित करेगा।

7.3 मद्दस्य एजेंसिया प्रतिमास दिलक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चा के व्याप्र-व्यैचित्रक समन्वयकारी सगठन को भेजेंगी। स्वैच्छित्रक समन्वयकारी सगठन ऐसे बच्चों के नाम तथा बड़े इर्षणी बाला रजिस्टर रखेगा तथा इसके अनिक्षिक बड़े भारतीय दिलक श्राही मान्यता-प्रिता का रजिस्टर रखेगा। स्वैच्छित्रक समन्वयकारी सगठन सभी मद्दस्य एजेंसियों के व्याप्रे परिचालित करेगा ताकि प्रतेक सगठन सभी बच्चों के सबध में उम भारतीय परिवार का जो बच्चे के दिलक ग्रहण के लिए किसी भी एजेंसी में मद्दस्य करना है पूरा विवरण उपलब्ध कर सके।

विविध

8.1 दिशा निर्देश का उपायन - यदि विदेशी गाज्य मरकार द्वारा विदेश म किसी भारतीय दूतावास के ध्यान में यह आता है कि कार्ड मान्यता-प्राप्त भारतीय एजेंसी या सूचीबद्ध विदेशी मगजन इन दिशा-निर्देशों के नभी या किसी प्रावधान को नहीं मान रहा है या इस प्रकार कार्य कर रहा है जो सामान्यन् बच्चा के हित म नहीं है तो उमके द्वारा सर्टिन तुरन्त कल्याण मवालय, भारत सरकार का सूचित करेगा।

8.2 मान्यता वापस लेना :—किसी भारतीय एजेंसी या किसी विदेशी एजेंसी की सूचाबद्धता मान्यता का अवधि के दौरान भारत सरकार के विवेक पर रद्द करने से पूर्व तुलशी का सम्मुचित अवसर दिया गया है।

8.3 दिशा नियमों में विवरण :—कल्पना सत्रालय, भारत सरकार भवन विवेक पर इन विवरणों में से एस सशाधन, परिवर्षन, रद्द कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है जो कि समय-समय पर आवश्यक रूप से जाए।

मार्शा शास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 4th July, 1989

RESOLUTION

No. 13-33/85-CHR(AC).—In their Judgements dated 6-2-1984, 27-9-1985 and 3-12-1986 in Writ Petition (CRL) No. 1171 of 1982 the Supreme Court have laid down the norms and principles that must be observed and the procedure that must be followed in every case of inter-country adoption of children. In order to facilitate the implementation of these norms, principles and procedures, the Government of India hereby issue guidelines on adoption children as per Annexure-I to this Resolution for the information and guidance of general public, voluntary agencies as well as all others concerned with the subject matter.

ANNEXURE-I

MINISTRY OF WELFARE GUIDELINES TO REGULATE MATTERS RELATING TO ADOPTION OF INDIAN CHILDREN

PREAMBLE :

1.1. Aims and Objects.—The Government of India recognises that the welfare of society, its growth and development depends to a great extent on the health and well-being of its children. The Constitution of India provides that the State shall direct its policy towards securing, inter alia that children are given facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. The National Policy for Children also recognises that the nation's children are a supremely important asset and that their nature and solicitude is the responsibility of the nation.

1.2. Need for Family Support for Development of Children.—It is an accepted fact that the balanced development of a child—emotional, physical and intellectual—can be best ensured within the family, or where this is not possible, in familial surroundings. The responsibility for providing care and protection to children including those who are orphaned, abandoned, neglected and abused rests primarily with the family, the community and society at large. However, since many traditional institutions including the family structure are undergoing changes on account of urbanisation, indus-

trialisation and the general process of development, family support to a child is not always available. It, therefore, becomes the responsibility of the community, of society and of the State to provide both institutional and non-institutional support to destitute children. Traditionally, our society has been providing support through charitable institutions and non-institutional activities like adoption, guardianship and foster care. Due to rapid changes in the social structure and other related factors, the number of children who need care, protection and rehabilitation is on the increase. It is, therefore, necessary not only to expand both institutional and non-institutional facilities for the nurture of such children, but also to regulate and monitor all programmes so as to ensure minimum standards in all child welfare activities. Among non-institutional modes, the interest of the child can best be served through adoption in a family. Further, it is also an accepted fact that the child develops best in his or her own cultural and social milieu. Thus, placement of a child through adoption in an indigenous setting would be ideal for his or her growth and development. Inter-country adoption, i.e., adoption of Indian children by adoptive parents residing abroad, should be resorted to only if all efforts to place the child with adoptive parents residing in India prove unsuccessful. Generally in all matters concerning adoption, whether within the country or abroad the welfare and interest of the child shall be paramount.

1.3. Review of Adoption Procedures.—The existing procedures and practices followed in the cases of inter-country adoption were thoroughly reviewed by the Supreme Court in their judgement dated 6th February, 1984, 27th September 1985 and 3rd December, 1986 respectively in Writ Petition (CRL) No. 1171/1982 by Shri Laxmi Pant Pandey. The Government of India after careful study of the Supreme Court Judgements hereby resolves to lay down the following guidelines for all concerned with a view to promote the welfare of children in general, and in particular, through adoption.

ROLE OF THE STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATIONS

2.1. List of Children's Homes.—The State Governments (the term "State Government" shall include Union Territory Administration wherever applicable) shall maintain a list of all Children's Homes being run for the maintenance of destitute, abandoned, orphaned, delinquent or neglected children by voluntary/private organisations which are registered, recognized or licenced under various laws.

2.2. List of Adoption Agencies.—The State Governments shall also separately maintain a list of all agencies handling in-country and inter-country adoption of children.

2.3. Inspection of Adoption Agencies.—The Governments shall periodically inspect all agencies and institutions handling in-country and inter-country adoptions as well as papers, documents, activities

connected with the services of children generally in order to verify :—

- (i) that adoption as an activity is being pursued by the organisation as a welfare measure in the interest of the child and not as a commercial activity;
- (ii) that proper records are being maintained for children admitted to the Homes;
- (iii) that the children admitted are provided with at least basic minimum standards for their care, protection, education and development;
- (iv) that lists of persons interested in adopting a child or taking a child under guardianship are being maintained by the organisation regularly;
- (v) that the accounts of the organisation are being maintained and audited annually without delay; that the auditor's reports are satisfactory; that any organisation which is in receipt of foreign funding is duly registered with the Ministry of Home Affairs and has otherwise complied with the provisions of the Foreign Contributions (Regulation) Act, 1976;
- (vi) that the organisation is making all efforts to encourage in-country adoptions and find parents for such children in India before resorting to inter-country adoption;
- (vii) that the organisation is receiving regular progress reports about the well-being of children given in adoption and takes adequate follow-up measures to safeguard their interest within the country and outside; and
- (viii) that qualified staff having social work experience continue to be employed to take care of the children.

2.4. Adoption Review Committee.—Each State Government shall set up an Adoption Review Committee chaired by a representative of the State Government. This Committee shall also include representatives of recognized Indian placement agencies, scrutinising agencies and as many experts in adoption and child welfare matters as are considered necessary. The Committee shall meet periodically to discuss child welfare measures, especially ways and means to promote in-country adoption of children. The State Government may also set up an Adoption Cell in the Directorate of Social Welfare to co-ordinate, regulate and develop the work of adoption and to render all assistance to the Adoption Review Committee.

2.5. Monitoring of Performance.—The State Government shall call for information and data every quarter from all agencies engaged in adoption in order to monitor and evaluate the functioning of these agencies. The data shall be called for in a

proforma to be prescribed for this purpose.

The State Governments shall take all such measures as are deemed necessary to actively encourage in-country adoption of children in preference to inter-country adoption and special attention shall be paid for rehabilitation of children in orphanages through placement by adoption.

ACTIONS PRESCRIBED UNDER THE JUVENILE JUSTICE ACT 1986

3.1 If any person, agency or organisation including all nursing homes and hospitals, religious institutions etc., come across abandoned or destitute children or find such children abandoned in his/their precincts or otherwise they shall immediately give information in regard to the discovery or find of such children to the Social Welfare Department of the concerned Government where such nursing homes or hospitals are situated in the capital of the State and in other cases to the Collector of the District and copies of such intimation will also be sent to the Foster Care Home where there is such a home run by the Government as also to the recognised placement agencies functioning in the city or town where such nursing homes or hospitals are situated and the Juvenile Welfare Board set up under the Juvenile Justice Act, 1986. The Social Welfare Department as also the Collector of the District will take care to ensure that this direction is followed by the nursing homes and hospitals etc., within their jurisdiction and if necessary intimation in regard to the discovery or find of abandoned or destitute children, if not sent by any particular nursing home or hospital to the Foster Care Home and the recognised placement agencies, shall be forwarded to them by the Social Welfare Department and the Collector of the District.

3.2 Procedure to be followed by authorised person etc.—If the person, agency or organisation who finds or takes the custody of an abandoned or destitute child has been authorised by the State Government to take charge of the abandoned/relinquished child, such person, agency or organisation shall take such action with regard to the abandoned infant as is required for dealing with neglected juvenile under the provisions of the Juvenile Justice Act, 1986 or any other law and also adequately identify the child with proper tag in case of infants.

3.3 Application for authorisation.—Any person, agency or organisation engaged in child welfare activities which intends to take charge of abandoned infants or neglected juveniles or to function as a place of safety or fit person/institution shall apply to the State Government concerned under the provisions of the Juvenile Justice Act, 1986 or any other law.

3.4 Maintenance and circulation of lists.—The State Government shall maintain a list of all such persons, agencies or organisation who have been authorised to take charge of abandoned children as neglected juveniles, or to function as places of safety or fit persons/institutions under the provisions of the Juvenile Justice Act, 1986 or any other law and shall furnish

the same to the police authorities and Juvenile Welfare Boards under whose limits these persons, agencies or organisations are located.

3.5 Personal appearance of child.—While intimating or reporting to the Juvenile Welfare Board or any other appropriate authority about the finding or coming in possession of an abandoned or destitute child, the personal appearance of the said child before the Juvenile Welfare Board or any other appropriate authority may not be necessary unless so directed by the Juvenile Welfare Board or any other appropriate Authority.

3.6 Control over fit person institution.—The State Government shall ensure that if any person, agency or organisation, including a nursing home, hospital, religious institution, etc., is found to indulge in sale, purchase, abuse, cruelty to or neglect of a child taken charge of in any manner strict action is taken against the individual(s) involved in accordance with law.

ROLE OF INDIAN AGENCIES ENGAGED IN ADOPTION OF CHILDREN

4.1 Listing with Authorities.—Every institution engaged in care and custody of children or in adoption work or any other activity related to orphaned, abandoned, destitute, neglected or relinquished children shall immediately get itself listed with the concerned State Government.

4.2 Only recognized agencies to undertake Adoption.—Any Indian desirous of undertaking inter-country adoption work shall apply for recognition to the Ministry of Welfare, Government of India and only such agencies as are recognised by the Ministry of Welfare, Government of India shall undertake inter-country adoption work.

4.3 Emphasis on child welfare.—Only such voluntary agencies as are primarily engaged in child welfare programmes for the growth and development of children and which undertake adoption as a part of their total activities may apply for recognition for inter-country adoption to the Ministry of Welfare.

4.4 List of prospective adoptive parents.—Every Social/Child Welfare organisation recognised for placement work in adoption shall regularly maintain a list of all prospective parents containing their names, addresses, date on which they have approached the organisation for taking a child in adoption and other relevant details.

4.5 Promotion of in-country adoption.—Every recognised agency shall make all efforts to find a placement for the child in adoption by an Indian family and shall also give all details about the child, including full details to the prospective adoptive family, except the name and address of the child's biological parents, where known to the recognised agency.

4.6 Record of promotion efforts.—Every recognised agency shall keep a complete chronological record of the efforts made by it for locating an Indian parent for the adoption of a child and shall specifically note down the reasons for any case of non-adoption of child by an Indian parents.

4.7 Case history.—Every recognised placement agency shall maintain separate file for each child with the child's complete case history.

4.8 Monthly quarterly data to be furnished to authorities.—Every recognised placement agency shall furnish monthly data to the Government of the State in which the agency is operating and a quarterly statement to the Ministry of Welfare, Government of India in such proforma as is prescribed by the Government in respect of children given to Indians and others for adoption.

RECOGNITION OF INDIAN AGENCIES

5.1 Proforma for application.—Any Indian Social/Child Welfare agency desirous of obtaining recognition from the Government of India for undertaking inter-country adoption work shall submit an application in the prescribed form to the Ministry of Welfare, Government of India, through the Department dealing with Social Welfare in the State in which the agency is located.

5.2 Un-recognised agencies barred.—No agency which does not hold a certificate of recognition from the Ministry of Welfare shall submit an application to an Indian Court under the Guardians and Wards Act, 1890, for declaring a foreigner as a guardian of an Indian child.

5.3 Recognition for specified period.—The Ministry of Welfare shall generally grant recognition to an agency for a specified period. This period may be extended by the Ministry pending issue of a recognition certificate.

5.4 Level of in-country adoption.—It shall be obligatory on the part of every recognised voluntary agency to arrange at least 25 per cent placements of children by way of adoptions/guardianship in Indian homes out of total placements effected by it by way of adoptions/guardianship in the first year of its recognition, and this level of in-country adoptions/guardianship shall be raised to 50 per cent by the third year of its recognition. The recognition is liable to be revoked in cases where the recognised agency fails to arrange in-country adoptions upto the figures stipulated above provided a reasonable opportunity of hearing has been given to the agency concerned before such recognition is revoked.

5.5 Conditions for recognition.—The voluntary agency which seeks recognition shall generally fulfil the following conditions :—

- It shall be a society registered under the Societies Registration Act, or a Trust created under the Charitable Trust Act; or an organisation registered under an appropriate law;
- The organisation shall be duly listed with the State Government as a child welfare organisation;
- It shall have a duly constituted Executive Committee; the Chief Executive of the organisation as well as the majority of mem-

bers of the Board|Executive Committee should be Indian Nationals;

- (d) It shall be an organisation duly listed with the State Government with appropriate arrangements for the protection and up keep of children, including infants;
- (e) The organisation should have been able to raise funds through public donations during the last three years; and
- (f) The organisation should have worked for the welfare of children during the last three years.

5.6 Agencies to maintain accounts.—(i) An agency shall maintain proper accounts to be audited by a Chartered Accountant every year.

(ii) A photostat copy of audited accounts together with audit report shall be furnished by every agency within one month from the date accounts have been audited by the Chartered Accountant, to the Social Welfare Department of the State Government concerned and to the Ministry of Welfare, Government of India.

5.7 Application to be processed only by recognised agencies.—An application for declaring a foreigner or an Indian to be the guardian of an Indian child as a prelude to adoption in a foreign country shall be processed only by a recognised Indian agency.

5.8 Application to be sponsored by enlisted foreign agencies.—A recognised Indian agency may submit an application of a foreign adoptive parent to an Indian Court for awarding the guardianship of an Indian child to a foreigner provided the application of such foreigner has been forwarded by a foreign voluntary agency enlisted by the Government of India. However, if there is an agency owned or operated by the Government in a foreign country, the foreign adoptive parents can approach a recognised Indian agency in India through such agency operated or owned by the foreign Government.

5.9 Indian agencies recognised to deal with approved foreign agencies.—No recognised Indian agency shall entertain any direct application for adoption of an Indian child from a foreigner or the foreigner's representative, except through a foreign agency 'enlisted' by the Government of India.

5.10 Inspection of agencies.—The premises of the recognised Indian agencies, including their Children Homes, and their records shall be open to inspection by officials of the Government of India and/or officials of the State Government at any time.

ROLE OF FOREIGN AGENCIES ENGAGED IN ADOPTION OF CHILDREN

6.1 Foreign agencies to apply to India's diplomatic missions.—A foreign Social|Child Welfare agency desirous of sponsoring applications of a foreign adoptive parents for adopting an Indian child shall make an application for enlistment with Government of India in the office of India's Diplomatic Mission in

that country and only such foreign agencies as are enlisted for this purposes by the Government of India shall undertake this activity.

6.2 Rights of child taken abroad.—On adoption of the child by the foreign parent according to the law of his/her country, it is presumed that the child would acquire the same status as a natural born child with the same rights of inheritance or succession and the same nationality as the foreign parent adopting the child.

6.3 Any foreign Social|Child Welfare agency enlisted by the Government of India may appoint a representative in India with the prior approval of the Ministry of Welfare, Government of India provided that such representative :—

- (i) is an Indian citizen;
- (ii) is qualified in social work and possesses experience in child welfare;
- (iii) represents only one foreign enlisted agency;
- (iv) restricts his sphere of operation to a particular geographical area in India; and
- (v) possesses the authority to operate a banking account in India in the name of the foreign enlisted organisation with the permission of the competent authorities.

6.4 All foreign enlisted agencies shall submit a half-yearly report in the prescribed proforma to the Ministry of Welfare, Government of India through India's Diplomatic Mission in the country where the agency is located.

VOLUNTARY CO-ORDINATING AGENCIES

7.1 Voluntary co-ordinating agency.—There shall be a centralized co-ordinating agency in the State or even in a large city where there are several social or child welfare agencies and each Social|Child Welfare agency shall provide information to the centralized agency in regard to the children available with it for adoption. The State Government shall take such measures as deemed necessary for the Constitution of Voluntary Co-ordinating Agency (VCA).

7.2 Annual meeting.—The Ministry of Welfare shall arrange every year a meeting of all Voluntary Coordinating Agencies for discussing matters of mutual interest and such other matters as are considered necessary and expedient.

7.3 The member agencies will send to the V.C.A. every month particulars of Children available with it for adoption. The V.C.A. shall maintain a register showing the names and particulars of such children and in addition it will maintain a register of Indian adoptive parents. The V.C.A. will circulate particulars to all the member agencies so that each agency is able to give full and detailed information in respect of all children to an Indian family which approaches any agency for the adoption of a child.

MISCELLANEOUS

8.1 Violation of guidelines.—If it comes to the notice of any State Government or any of India's Diplomatic Missions abroad that a recognised Indian agency or an enlisted foreign agency respectively is not observing all or any of the provisions of these guidelines, or is otherwise functioning in a manner which is not in the interests of children generally, it shall inform, the Ministry of Welfare, Government of India, immediately with details thereof.

8.2 Withdrawal of recognition.—The recognition granted to any Indian agency or the enlistment of any

foreign agency may be revoked during the period of recognition at the discretion of the Government of India, provided a reasonable opportunity has been given to the agency concerned to be heard before such recognition/enlistment is revoked.

8.3 Amendment to guideline.—The Ministry of Welfare, Government of India, shall at its discretion, make such amendments, additions, deletions or alterations in these guidelines as are deemed necessary from time to time.

ASHA DAS, Jt. Secy.

